

सरकार नहीं खर्च कर पारही पैसा, तो सप्लीमेंट्री बजट क्यों : अखिलेश यादव

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को मंहगाई, स्वास्थ्य सेवाओं, गौशालाओं में मर रहे गोवंश, सड़कों के गड्ढों, बिजली समेत अन्य मुद्दों पर भी जमकर घेरा। अखिलेश ने सदन में अनुपूरक बजट पर योगी सरकार से पूछा कि जब पहले का धन ही सरकार खर्च नहीं कर पा रही है तो आखिरकार सल्लीमेंट्री बजट क्यों लाया गया। पहले बजट का लगभग 63 परसेंट पैसा खर्च नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी है, उसमें भी भी 65 परसेंट पैसा पड़ा हुआ है जो खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था क्या इस सल्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो यह लगता है कि पांच साल पहले का कार्यकाल और लगभग दो साल इस सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, यह सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब मुख्य बजट से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यह सल्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? जब आपके बजट की तुलना होती अन्य प्रदेशों से होती है तो 18वां स्थान है आपका। यह आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं हैं। इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया, जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए। ना नया बनाया ना पुराने अस्पतालों में सुधार किया। उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, सरकार हिस्टोरिकल लूट कर रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया। सरकार की नजर पड़ गई तो थोड़ा बहुत बचा होगा। सरकार बताए कि आप मेट्रोनेस और गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो



सरकारी कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाया गया एक्सप्रेसवे घाटे का है। आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे घाटे का है कि फायदे का है। आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राझिंडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वह समाजवादियों का बनाया गया एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा कि घोड़ा समझ लेता है घुड़सवार कैसा है। अधिकारी भी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। कहाँ पहुंच गई है महारांगी, अधिकारक इसको मुनाफा कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? गोवंश भूखे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और अधिकारी मिलकर चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बाजारों में सांड, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड, किसान की कितनी जान जा चुकी है। आज 7 साल पूरे होने वाले हैं बताइए सरकार को बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश में कितना बढ़कर मिला? जो मेट्रो चल रही है सब समाजवादियों की देन है। मुख्यमंत्री जी आप अपने यहाँ तो मेट्रो बना लो कहाँ मेट्रो वाली बात वैसी तो नहीं है 46 में 56 वाली बात जैसी? किसानों को समस्या पर अखिलेश ने कहा कि जो यहाँ (सदन) पर खेती करने वाले लोग हैं। अगर कहाँ धान खरीदा गया हो तो बता दो। जहाँ पर धान खरीद हो रही है वहाँ पर लगाइए सीसीटीवी, क्यों नहीं लगाते हैं आप। क्यों द्रांस्यायरेसी नहीं चाहते हैं, क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं? सरकार ने किसानों की एक मंडी बनाई हो तो बता दें। इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है? अखिलेश यादव ने कहा कि 41 मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बचाई और उनको बचाने में जो-जो एजेंसी थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रैट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में धुसकर गए और उन्हें बचा कर लेकर आए। दिल्लियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले, बड़ी-बड़ी डिगे हाकने वाले लोग क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे अप। उन्होंने कहा कि एक गरीब किसान से बीजेपी के लोगों ने जमीन लिखवा ली, छह करोड़ का उसको चेक दे दिया। उसके बाद कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है वापस दे दो, उसका चेक फाई कर फेंक दिया। वह भटकता रहा, पुलिस के पास गया कोई अधिकारी नहीं बच्चा, उसने ऐसा कोई नहीं जिसका दरवाजा न खटखटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला और मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। अखिलेश ने अखिलेश में जातीय जनगणना को लेकर कहा कि पूरा देश चाहता है कि जातीय जनगणना हो। अंततेगत्वा यह बीजेपी के लोग भी जातीय जनगणना में खड़े हो जाएंगे, देखिएगा। यह समय आएगा की बीजेपी के लोग भी कहेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।

गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील पासवान के मामले की हाई कोर्ट में अगली सुनवाई चार को

रांची, (हिस.)। ज़ारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील कुमार पासवान की ओर से उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद्द करने के आदेश के खिलाफ दावर अपील पर सुनवाई हुई। मामले में मेटिबिलिटी (याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं) पर सुनवाई जारी रही। राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई। इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई 4 दिसम्बर निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने परवै की। प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया था कि इनके पिता वर्ष 1982-83 में सरकारी सेवा पर रहते हुए सचिव, व्यापार मंडल गिरिडीह के पद पर थे। प्रार्थी की शिक्षा- दीक्षा एवं लालन पालन गिरिडीह में ही हुआ है। इस दौरान गिरिडीह के सक्षम प्राधिकार द्वारा इनका जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया था। इन्होंने मुख्यांश का चुनाव सहित कुछ अन्य जनप्रतिनिधि का इलेक्शन लड़ा था लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल नहीं उत्तया गया था। मेयर का चुनाव लड़ने



के बाद जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया गया। एकीकृत बिहार के समय से वह गिरिडीह में ही थे। इसलिए अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर उनके द्वारा मेयर का चुनाव लड़ने का आरोप गलत है। उन्हें मेयर पद के अयोग्य घोषित किया जाना गलत निर्णय था।

एकल पीठ ने इस संबंध में प्रार्थी सुनील कुमार पासवान की रिट याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि अन्यमन्त्रित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद पर सुनील कुमार पासवान का चयन वर्ष 2018 में हुआ था। उनके खिलाफ जामुमो कार्यकर्ता ने उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद गिरिडीह डीसी ने जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद कर दिया था। डीसी ने दो दिसम्बर, 2019 को पत्र के माध्यम से सरकार को बताया कि प्रमाण पत्र में अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। बाद में ज्ञारखण्ड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत पासवान को पद से विरामित कर दिया गया था।

वह दिन दूर नहीं जब देश वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त होगा : अमित शाह

हजारीबाग (झारखण्ड), (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वे झारखण्ड में हैं। कल ही उन्होंने देशभर में वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर जो लड़ाई चल रही है उसकी समीक्षा की। वे देश की जनता को बताना चाहते हैं वह दिन दूर नहीं जब देश वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री शुक्रवार को हजारीबाग के मेरु स्थित सीमा सुरक्षा बल केंद्र में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि आज वे विश्वास से कह रहे हैं कि विगत 10 वर्षों में भारत सरकार के प्रयास से हिंसा की घटना में कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद सिमटता जा रहा है। हिंसा पर प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार हैं। हम आने वाले दिनों में वामपंथी के उग्रवाद से देश को मुक्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों का ही प्रयास है कि बुढ़ापहाड़ को उग्रवाद से मुक्त करने के लिए सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों की जमकर सराहना की उन्होंने कहा कि 'जीवन पर्यन्त कर्तव्य' केवल बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है, बल्कि अपने



आप को चरितार्थ भी किया है। साथ ही कहा कि बीएसएफ के लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का स्वर्णकाल 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के रेंगिस्तान में, कहीं हरामी नाला की दलदलों में तो कहीं बंगाल की सुंदरनगर के जल में बिताया है।

परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है। शाह ने कहा कि पूरा देश बीएसएफ के जवानों को सलाम करता है और नाज करता है। आपके मोर्चा संभालने के बाद किसी के देश सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है अप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पर्ति के प्रहरी हैं। आप दिवाली का दीया सरहद पर जलाते हो, होली सरहद पर मानते हो। आप सीमा पर होते हैं तभी हम घरों में सुकून से रह पाते हैं। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता। पूरा देश और विशेषकर मैं गृह मंत्री आप बरबाद नाज करता हूँ, गर्व करता हूँ शाह ने कहा कि

गौतम बुद्ध ने विश्व को दिया शान्ति का संदेश : राज्यपाल

सिद्धार्थनगर, (हि.स.)। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदेबेन पटेल ने कहा कि यह बुद्ध की पावन धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करती हूँ। यहां पर गौतम बुद्ध ने विश्व को शान्ति का सन्देश दिया। यह भूमि देश-विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सप्तम दीक्षांत समारोह के अवसर पर शुक्रवार को स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोग शिक्षा प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन करें समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने माता-पिता से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। रात-दिन मेहनत करके माता-पिता हमें शिक्षा दिलाते हैं। हमारा दायित्व है कि हम अनन्तकाल तक उनकी सेवा करें। आज दहेज प्रथा हमारे समाज में एक अधिष्ठाप है। दहेज के लिए बहुओं के साथ मारपीट करते हैं। हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। अपनी बहुओं का सम्मान करना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना चाहिए। आज का युवा देश का भविष्य है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाना है। मुख्य अतिथि एवं कुलपति युजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रो. रमाशंकर दुबे ने कहा कि अतीत काल से ही प्रकृति के सुरम्य अँचल में, पर्वत राज हिमालय की तलहटी में धने जंगलों से आच्छादित, शाक्यगण की राजधानी बौद्ध धर्म



के संस्थापक भगवान बुद्ध के बाल्यकाल और जीवन को समेटे हुए इस सिद्धार्थ नगर की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। सत्य, अहिंसा प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान से विश्व को आलोकित करने वाले भगवान बुद्ध के दर्शन और उपदेश की परम्परा और विरासत को सजोये हुए है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षितज पर अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षान्त समारोह एक पावन समारोह होता है। सभी उपाधिधारकों का आह्वान करता हूँ कि आप अपने जीवन में सदैव स्मरण रखें कि आपने ऐसे विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, जिसकी स्थापना त्याग-तपस्या, हिंसा, करुणा और शांति के महान उपदेशक स्वयं भगवान बुद्ध के नाम पर हुई है। छात्र-छात्राओं आप याद रखें कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने भगवान बुद्ध बनकर अपने तपोनिषट जीवन के अनुभवों के आधार पर जिन आदर्शों को जीवत रखा और मानव कल्याण हेतु शिक्षा का सन्देश दिया आप भी उन आदर्शों को अपने जीवन में आमसंतान करें। मुझे अतिशय प्रसन्नता है। डिग्री होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, स्नातक एवं परास्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्नातकत एवं स्नातकोत्तर में कुल 46 स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

केंद्रीय एजेंसियों को भेजी जाएगी
गैंगस्टरों की अवैध सम्पत्तियों की डिटेल

मुरादाबाद, (हि.स.)। सिविल लाइस थाना क्षेत्र में हुड़ी स्पोर्ट्स व्यापारी कुश-कंक गुप्ता की हत्या और मझोला थाना क्षेत्र में सीए श्वेताभ तिवारी की हत्या और भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या से पूरा जिला हिल गया था। इन हत्याकांडों को गिरोह बनाकर गैंगस्टरों ने अंजाम दिया था और अकूत धन अर्जित किया था। उन पर पुलिस लगातार लगाम कस रही है। अब पुलिस ऐसे गैंगस्टरों की सम्पत्ति का ब्लोरा केंद्रीय एजेंसियों को भी भेजने की तैयारी कर रही है।

पांच राज्यों के एकिजट पोल भाजपा के लिए उत्तराहन्तक : अर्द्धत संदर्भ

उत्तर प्रदेश में अल्पविकसित वी मलिन बस्तियों के विकास पर योगी सरकार का फोकस

- सीएम योगी के विजन अनुसार प्रदेश की बस्तियों में 98 कार्यों के जरिए कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश को विकास व उन्नति के नए पथ की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार प्रदेश में अल्प विकासित व मलिन बस्तियों में विकास कार्यों को पूर्ण करने पर भी फोकस कर रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार, प्रदेश के अल्प विकासित क्षेत्रों में विकास की बयार को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसको क्रियान्वित करते हुए अब प्रदेश में 98 विकास कार्यों के जरिए कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अमरोहा तथा देवरिया में जिन 28 विकास योजनाओं की पूर्ति को हरी झँडी मिल गई है। उनमें अमरोहा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले हसनपुर, अमरोहा व गजरौला क्षेत्रों में 6 विकास कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। बहाँ, देवरिया के सलेमपुर, रुद्रपुर, भलुअनी, रामपुर कारखाना व गौराबरहज में कुल 22 इंटरलॉकिंग, सीसी रोड व नाली निर्माण की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए 6.89 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसमें से पहली किस्त पर 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन का मार्ग

प्रक्रिया को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत फरुर्खाबाद, अयोध्या, मीरजापुर, पीलीभीत व गाजियाबाद में 70 विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 12.03 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

जिसमें से पहली किस्त 40 प्रतिशत यानी 4.81 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसमें फरुर्खाबाद में कुल 14 अलग-अलग परियोजनाओं की पूर्ति के लिए 7.7 करोड़ रुपए के सापेक्ष 3.1 करोड़ रुपए, अयोध्या में कुल 15 परियोजनाओं के लिए 1.35 करोड़ रुपए के सापेक्ष 54 लाख रुपए, मीरजापुर में 3 परियोजनाओं के लिए

व फरुखाबाद, अगोद्धा, मीरजापुर, पीलीभीत व गाजियाबाद में 70 विकास कार्यों को पूर्ण करने का रास्ता साफ हो गया है। इस क्रम में, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग ने कारवाई शुरू कर दी है तथा शासन से भी धनराशि आवंटन के अंतर्गत पहली किस्त जारी करने की प्रशस्त करते हुए कुल 5.17 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। अमरोहा में विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए 1.59 करोड़ रुपए के सापेक्ष 1.19 करोड़ तथा देवरिया में 5.30 करोड़ रुपए के सापेक्ष 3.98 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के तौर पर जारी कर दी गई है। 91.12 लाख रुपए के सापेक्ष 36.44 लाख, पीलीभीत में 9 परियोजनाओं के लिए 1.12 करोड़ रुपए के सापेक्ष 45.09 लाख रुपए तथा गाजियाबाद में 29 परियोजनाओं के लिए 6.05 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2.42 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के तौर पर जारी कर दी गई है।

बकाया मांगने पर रंगदार की तरह व्यवहार करती है केन्द्र सरकार: मख्यमंत्री

A photograph of a political rally. In the center, a man in a light blue shirt and white dhoti is standing behind a black podium, gesturing with his right hand. To his left, another man in a grey suit is seated. Behind them is a large red banner with white text that reads 'आपका योजना आपकी सट्टकार परकेता'. The background features a yellow wall with a green and blue decorative panel showing a landscape. The overall atmosphere is that of a formal political event.

देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है बिहार का अतैध मुसिचूद और महाराजा गिरियाज़ सिंह

बेगूसराय, (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिराज सिंह ने बिहार के सीमांचल में तेजी से बढ़ रहे अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री से किया है। गिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाएं। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि ना धर्म बचेगा और ना ही धन। बिहार में लगभग तीन हजार मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए। धार्मिक ब्रेनवाश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बढ़ा आ गई है। बिहार, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डर सीमांचल इलाकों में और अधिक कब्जा हो गया है। यह सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है।

पीएफआई बिहार में काफी सक्रिय है, बिहार में मुसलमान की आबादी 18 प्रतिशत है। इस अवैध करजे को बंद कर मस्जिदों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत कार्रवाई करते हुए इस अवैध मस्जिद और मदरसों को बंद कराएं। बोट के लालच में बहत हो गया है।

नीतीश कुमार अब बिहार और देश के आंतरिक खतरों पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बिहार के लोगों का धर्म, धन और संस्कृति खतरा में पड़ जाएगा। इसके लिए दोषी होंगे नीतीश कुमार और लालू यादव। नीतीश कुमार तुष्टिकरण की इस निंदा से उठें और देश को आंतरिक सुरक्षा के खतरा से सरक्षित करें।

आज यहाँ पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए पांच शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए उन्होंने कहा कि शहीद के परिवारों को मैं कहन चाहता हूँ कि आपके परिवार का जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं है लेकिन 13 करोड़ की जनत आपके परिवार के बलिदान पर हमेशा गर्व करती है। हमेशा यह इतिहास बनाने पर दर्ज सहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे जी 20 की बैठक में देश के ध्वज को समस्त विश्व में लहराना हो। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से पांचवें नंबर पर पहुंचाना हो। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा विकास और लोकतंत्र की प्रक्रिया तीनों को बढ़ावा दिया गया। सीमा के क्षेत्र में हजार करोड़ की बजट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरूआत हुई। सीमा वाले क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत हुई।

बेगूसराय, (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिराज सिंह ने बिहार के सीमांचल में तेजी से बढ़ रहे अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री से किया है। गिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाएं। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि ना धर्म बचेगा और ना ही धन। बिहार में लगभग तीन हजार मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए। धार्मिक ब्रेनवाश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बढ़ा आ गई है। बिहार, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डर सीमांचल इलाकों में और अधिक कब्जा हो गया है। यह सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है।

पीएफआई बिहार में काफी सक्रिय है, बिहार में मुसलमान की आबादी 18 प्रतिशत है। इस अवैध करजे को बंद कर मस्जिदों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत कार्रवाई करते हुए इस अवैध मस्जिद और मदरसों को बंद कराएं। बोट के लालच में बहत हो गया है।

नीतीश कुमार अब बिहार और देश के आंतरिक खतरों पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बिहार के लोगों का धर्म, धन और संस्कृति खतरा में पड़ जाएगा। इसके लिए दोषी होंगे नीतीश कुमार और लालू यादव। नीतीश कुमार तुष्टिकरण की इस निंदा से उठें और देश को आंतरिक सुरक्षा के खतरा से सरक्षित करें।

संपादकीया

मौत की सूरंगें

उत्तराखण्ड की उत्तरकाशी सुरंग के निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं
और अहम शर्तों, प्रावधानों की अनदेखी पर सवाल करना
उतना ही उचित है, जितना फंसे 41 मजदूरों की जिंदगीं बचाना जरूरी था।
चूंकि सर्वोच्च अदालत उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाने और मार्गों के
विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके फैसले आते रहे हैं कि निर्माण-कार्य,
मानकों की तुलना में, घटिया स्तर के हैं, लिहाजा पहाड़ और मानवीय जीवन
लगातार खतरे में बने रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने फैसलों के अलावा, विशेषज्ञ
समितियां भी बनाई, लेकिन सभी के निष्कर्ष कमोबेश यही रहे हैं। अलवत्ता वे
पहाड़ में निर्माण और खुदाई के खिलाफ नहीं थीं। उत्तराखण्ड में औसतन 6 करोड़
पर्यटक सालाना जाते हैं, जिनसे करीब 15,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता

सर्वोच्च अदालत उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाने और मार्गों के विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके फैसले आते रहे हैं कि निर्माण-कार्य, मानकों की तुलना में, घटिया स्तर के हैं, लिहाजा पहाड़ और मानवीय जीवन लगातार खतरे में बने रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने फैसलों के अलावा, विशेषज्ञ समितियां भी बनाई, लेकिन सभी के निष्कर्ष कमोवेश यही रहे हैं। अलबता वे पहाड़ में निर्माण और खुदाई के खिलाफ नहीं थीं। उत्तराखण्ड में औसतन 6 करोड़ पर्यटक सालाना जाते हैं, जिनसे करीब 15,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। उनमें काफी पर्यटक चारधाम की यात्रा भी करते हैं, लिहाजा वे सुरंगों को पार करके ही केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को जोखिम में धकेला जा सकता है? विवादित सुरंग के संदर्भ में सबसे अहम सवाल ‘आपातकालीन निकास मार्ग’ का है। विपक्ष ने भी ये सवाल उठाए हैं। वे गलत नहीं हैं। फैसले हुए मजदूर बाहर निकले जा चुके हैं। ‘चूहा खनिकों’ को पुरस्कार के तौर पर 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की जा चुकी है। विपक्ष की राजनीति को एक तरफ रख भी दें, तो सुरंग की योजना से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे 3 निकास-मार्ग बनाए जाने थे, लेकिन कंपनी ने आज तक एक भी मार्ग और द्वार नहीं बनाया है। विशेषज्ञों ने भी निरीक्षण में अनदेखी बरती है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि सुरंग परियोजना की ईपीआर और निर्माण-कार्य में गहरे अंतर हैं। फिलहाल निर्माण कंपनियां और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय आदि खामोश हैं। यदि सरकारी वेबसाइट पर निर्माण-योजना को पढ़ें, तो स्पष्ट होगा कि यह तय किया गया था कि सुरंग, बाहर निकलने का रास्ता और अप्रॊच रोड 8 जुलाई, 2022 तक बन जाएंगे। इस परियोजना पर काम विपक्ष ने भी ये सवाल उठाए हैं। वे

यित्यादि ना था पर सतीता उड़ाइ है। पर गलत नहीं है। फैसले हुए मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। 'चूहा खनिकों' को पुरस्कार के तौर पर 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की जा चुकी है। विपक्ष की राजनीति को एक तरफ रख भी दें, तो सुरंग की योजना से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे 3 निकास-मार्ग बनाए जाने थे, लेकिन कंपनी ने आज तक एक भी मार्ग और द्वार नहीं बनाया है।

हकीकत यह है कि सुरंग में बचाव का कोई भी रास्ता आज तक नहीं बनाया गया है। कपनी की अपनी दलील है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लेन के बीच दीवार है। उसमें ‘आपातकालीन निकास-द्वार’ का प्रावधान है। एक से दूसरी तरफ आया-जाया जा सकता है, लेकिन यह भी हकीकत समझने आई है कि सुरंग में कहीं भी निकास-द्वार अभी तक नहीं बनाया गया है। सुरंग के खोदे गए हिस्से में भी ‘सुरक्षा-पाइप’ नहीं डाले गए हैं। इस परियोजना से जुड़े प्रबंधकों की सफाई है कि कमज़ोर स्थानों पर ‘सुरक्षा-पाइप’ का इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं था कि ऐसा हादसा होगा ! खतरों और हादसों के भी एहसास होते हैं क्या ? पर्यावरण संबंधी सरोकार सर्वोच्च अदालत ने भी जाता थे। आज भी ये चिंताएं अपनी जगह मौजूद हैं। निर्माण से जुड़ी 10 कंपनियों में सेंजिस ‘नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड’ को 853.79 करोड़ रुपए का उप-ठेका दिया गया, उसके दामन पर हादसों और मौतों के दाग पहले से ही हैं। फिर भी यह ठेका दिया गया, लिहाजा यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। हादसे की जांच समिति का नेतृत्व निदेशक, भूस्खलन शमन और प्रबंधन केंद्र, उत्तराखण्ड कर रहे हैं। समिति में किसी भी भू-विज्ञानी को नहीं रखा गया है। सिर्फ 6 इंजीनियर हैं और श्रमिक संघ या स्वतंत्र विशेषज्ञ भी नहीं हैं। जांच समिति भी सवालों में है। ‘चूहा-खनिकों’ के मेहनताने का मुद्दा भी उठा है। इससे जुड़े कानून कागजों पर तो है, लेकिन कोई भी नियामक या आयोग नहीं है।

कुछ

अलग

बल्लारिया का सिनेमा

पूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में बसा बल्लारिया, रिपब्लिक ऑफ

बल्लारिया के नाम से ऑफिसियली दर्ज है। पूरोप महादेश का एक प्राचीनतम देश कई लोगों द्वारा शासित हो, अंततः आज एक स्वतंत्र देश है। एक समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा बल्लारिया द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद काफी समय कम्युनिस्ट देश रहा। अरसी के दशक के अंत और नब्बे के प्रारंभ में यह छिटककर अलग हुआ। 2004 में एनएटीओ का सदस्य बना और 2007 में यूरोपियन यूनियन से जुड़ गया। बल्लारिया की प्राकृतिक सुषमा आकर्षक है और यहाँ संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। स्लाविक समुदाय लोकल समुदाय से घुलमिल गया है। साथ ही तुर्क, रोमा, अर्मेनियन, रूसी, यूनानी, तातार भी हैं। बल्लारियन भाषा और कई बोलियां यहाँ प्रयुक्त होती हैं। लोककथाओं, लोकगीत, उत्सवों, गुलाब का इत्र बनाने के साथ लाइबेरी, ऑपेरा, कल्चरल इंस्ट्यूशन, थियेटर, संगीत यानी सांस्कृतिक रूप से खूब समृद्ध देश बल्लारिया के रचनाकार एंलियास कैनेटी को 1981 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोफिया इसकी राजधानी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बल्लारिया का फिल्म उद्योग काफी फलाफूला, यहाँ बनी डॉक्यूमेट्री की खूब पूछ रही है। एनीमेटेड कार्टून खूब पसंद किए जाते हैं। यहाँ के दर्शक देश-विदेश दोनों स्थानों की फिल्मों में रुचि रखते हैं। लेकिन नब्बे के दशक में यहाँ का फिल्म उद्योग एक बार भहरा गया। वैसे सोफिया में प्रतिवर्ष इंटरनेशनल फिल्म समारोह होता है। अधिकांश फिल्में सोफिया के नजदीक बने राज्य द्वारा संचालित बोयानाफिल्म स्टूडियोज में बनती हैं। वैसे तो अन्य देशों की भाँति 1996 में ही बल्लारिया में फिल्म पहुंच गई। 1915 में स्क्रीनराइटर, डॉयरेक्टर तथा अभिनेता वैसिल गेड्वेक का

लिखा- 'बल्लारियनफिल्म ! ब्लारिट अंडर बल्लारियन स्कार्फ जनवरी 1915 को बल्लारियन फिल्म 'बल्लारियन इज गैलान्ट' न पढ़े पर थी। आज इसका नाम हिस्सा उपलब्ध है बाकी द्वितीय में सोफिया पर हुई बमबारी में नष्ट कॉमेडी फिल्म का बचा हुआ हिंदू तो इतना मजा आएगा, जो शायद फिल्मों को मात कर दे। वैसिल इस मूक फिल्म में एक मनचल एक लेडी को फँसाने के चक्रकर तरह फंस जाता है। वह लेडी नचाती है, उसके खूब रकम खच्च है, उसका कुली की तरह उपयोग और अंत तो आपको खुद देखना है की भूमिका में मारा लिपिना है। निर्देशक वैसिल गेड्वेक स्वयं है अन्य फिल्म कारों को उनकी सहयोग मिला वैसे ही इस निर्देश मिला। फालके तथा सत्यजित रामने अपने आभूषण बेच कर अपने फिल्म बनाने में सहयोग दिया था गेड्वेक की पत्नी ज्ञाना ने उसे पहले बनाने में आर्थिक योगदान किया दोनों ने मिल कर 'यंत्र फिल्म' नींव डाली, यह बल्लारियन प्रोडक्शन हाउस था। इन्हीं लोदेश की पहली सवाक पिस्ताव 'स रिवोल्ट' बनाई। इस इहोंने बल्लारिया के नेशनल स्वतंत्रता सेनानी वैसिल लेव समर्पित किया। फिल्म को लेव विवाद भी हुआ। फिल्म की ही आज इस सेनानी का घर एक है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन पति-पत्नी को वह सम्मान जिसके ये हकदार थे। लेकिन सत्य है, आज उन्हें बल्लारियन संस्थापक माना जाता है।

बल्गारिया का सिनेमा

अलग

सिलव्यारा का सबक नहीं सीखा तो भयंकर होंगे परिणाम

सारे देश का हल्ला दन वाल सिलक्यारा सुरंग संकट का सुखान्त पटाक्षेप हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस हादसे के अनुभव से हमारे भूविज्ञानियों, खनन विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन तंत्र ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। साथ ही हमारे राजनीतिक शासकों और योजनाकारों को भी हिमालय पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट थोपने पर नए सिरे से विचार करना होगा। अपने बेवाक कथनों के लिए चर्चा में रहने वाले केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तो सार्वजनिक रूप से अपनी ओर से हुई चूक को कबूलने के साथ ही हिमालयी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख भी कर चुके हैं। अगर पहले के अनेक हादसों की तरह कुछ दिन बाद फिर सिलक्यारा की दुर्घटना की बात आई गई हो गई तो फिर भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को कोई नहीं रोक सकता। दरअसल पिछले ही साल 19 मई को जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर रामबन में एक सुरंग निर्माण के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से 10 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इसी उत्तराखण्ड में टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के समय 1 अगस्त 2004 को सुरंग में काम चलने के दौरान हुए हादसे में 29 मजदूरों की जानें चलीं गई थीं। सुरंग निर्माण के दौरान अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती हैं जिनसे निपटने के लिए अनुभव और क्षेत्र विशेष की भूर्भीय स्थिति की सही जानकारी होनी चाहिए। मगर अनुभव बताता है कि विभिन्न कारणों से लापरवाहियों से सुरक्षा मानकों की निरन्तर अवहेलना होती रही है। स्वयं केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इस संवेदनशीलता का उल्लेख कर सावधानी बरतने की बात कह गए हैं, लेकिन योजनाकार और योजनाएं बनवाने वाले इस हकीकत की अनदेखी करते रहे हैं। टिहरी बांध परियोजना की भूमिगत खुदाई के दौरान 2004 में हुए हादसे के कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त, 2004 को कुललू से लगभग 60 किमी दूर हिमाचल प्रदेश में पारबती जल विद्युत परियोजना में एक सुरंग के अंदर बीस श्रमिक फंस गए थे जिन्हें सिलक्यारा की तरह बचा लिया गया। इसी तरह 14 फरवरी 2010 को हिमाचल प्रदेश के ही किन्नौर जिले में 1,000 मेगावाट की पनविजली परियोजना कर्त्रम वांगत में बांध निर्माण के लिए किए गए विस्कोट काम से आस्थर पत्थर और बाल्डर श्रमिकों का एक अस्थायी बस्ती पर गिर गए। जिससे 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 2015 में उसी किन्नौर जिले में एक और त्रासदी में, शोटोंग-करचम परियोजना में एक विस्कोट में दो श्रमिकों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। ऐसे हादसों में मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या में हमेशा विवाद रहता है। अगस्त 2004 को टिहरी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल टी-3 में चट्टाने खिसकने से मरने वालों का अधिकारिक संख्या 29 बतायी गई थी जबकि उस समय वहां कम से कम 109 लोगों के मौजूद होने की बात सामने आई थी। इसी साल 19 जुलाई का चमोली कस्बे में बिजली का करंट से मरने वालों की संख्या 16 बताई गई थी लेकिन अपृष्ठ समाचारों में यह भी कहा गया था। विकुछ लोगों ने जान बचाने के लिए हड्डबड़ी में उफनन्त अलकनन्दा में छलांग लगा दी थी। दरअसल निर्माण कार्य बहुत दूर-दराज के इलाकों में होते हैं, इसलिए क



भूविज्ञानियों, खनन विज्ञानी और आपदा प्रबंधन तंत्रज्ञानी होते कुछ सीख लिया होगा। इसी हमारे राजनीतिक विद्यों को और योजनाकारों को भवित्व देता है। इसीलय पर अपने द्रीम प्रोजेक्ट के बाहरी पर नए सिरे से विचार करना होगा। अपने बेवकूफ कथन के एवं वर्चामें रहने वाले केन्द्रीय विधायक परिवहन और राजमार्ग निर्माण नितिन गडकरी तो जनिक रूप से अपनी ओर रख लेते हैं। अगर पहले के अनेक विद्यों को कबूलने के साथ ही उल्लिखित क्षेत्र की विशेष स्थितियों का उल्लेख भी करना चाहिए है। अगर पहले के अनेक विद्यों की तरह कुछ दिन बाद सिलकायरा की दुर्घटना की आई गई हो गई तो फिर वह मैं ऐसे हादसों की विवरिति को कोई नहीं रोक

सिलक्यारा सुरग
क्षेप हो गया है।

पर कलस्टर के अहैया करवाई जा रही

प्रार्थामक शिक्षा का नक्ष छाव

स्कूलों शिक्षा के चरम बिंदु पर कलस्टर के अधीन प्राथमिक स्कूलों को छांव मुहेया करवाई जा रही है, यानी कुछ ऐसी सीडियां विकसित की जा रही हैं जो व्यवस्था को मुकम्मल करेंगी। राज्य के जमा दो, हाई व मिडल स्कूल अपने दायरे के आधा किलोमीटर तक आने वाले प्राइमरी स्कूलों के अभिभावक बन जाएंगे। इस तरह अब करीब पांच हजार संस्थानों के तहत शिक्षा की बुनियादी प्रश्न हल होंगे, हालांकि अतीत में भी एक ही स्कूल के तहत छात्र जीवन की सीडियां मुकम्मल होती थीं। शिक्षा की मात्रात्मक वृद्धि ने अब फिर गुणात्मक अर्थ पुँजा करने के लिए उन्हीं रास्तों को चुना है, जो पहले मंजिलों के बाहक रहे। जाहिर है कलस्टर पद्धति से शिक्षा का उच्चारण ही एक जैसा नहीं होगा, बल्कि प्रबंधन, अनुशासन व वित्तीय उपयोगिता भी बढ़ेगी। यानी बिखरे हुए स्कूलों के अंदर ज में कुछ तो फर्क आएगा, फिर भी शिक्षा क्षेत्र में वायित्व की ओवरलैपिंग के कारण सारी वर्णमाला बदल गई है। मॉडल कंपोजिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कई संदेश निकलते हैं। पहला यही कि हिमाचल में अनावश्यक विस्तार ने अधोगति तक पहुंचा दिया। दूसरे यह कि वित्तीय व्यवस्था में अब ऐसे अर्थहीन व्यय नासूर बनने लगे। तीसरे यह कि शिक्षा की मांग व आपूर्ति में गुणवत्ता की अर्हताएं पूरी नहीं हुरझ़। चौथे शिक्षकों की जवाबदेही परीक्षा में तो देखी गई, लेकिन अध्यापन को किसी सांचे में नहीं ढाला गया। हर बार शिक्षा मुड़-मुड़ कर अपने ही खोए हुए अतीत से कुछ पाना चाहती है और इस बार भी यही सब हो रहा है। शिक्षा विभाग कालेज व विश्वविद्यालयों की तर्ज पर 'अतिथि शिक्षकों' की खेप उतारने की ओर अग्रसर हो रहा है। देखना यह होगा कि इस पहल से शिक्षा की मांग की आपूर्ति कैसे होती है। बेशक कुछ शिक्षक आज भी बच्चों के आदर्श बनकर प्रभावित करते हैं और अगर इनकी सेवाएं सेवानिवृत्ति के बाद भी यथावत रहती हैं, तो छात्रों का विश्वास पद्धति पर ही बढ़ेगा। यूं भी शिक्षा अपने सुधार के मजमून में हर बार नया श्रृंगार करती रही है, लेकिन कुछ सफे हमेशा काले निकल आते हैं। हिमाचल में शिक्षा को स्कूलों में स्तरोन्नत किया गया और इसी वजह से गांव तक पाठशाला की पहुंच व उसके स्तर में निखार आ गया, लेकिन अध्यापन के चरित्र में गिरावट आ गई। आज भी अगर नया संकल्प कलस्टर के जरिए गुणात्मक शिक्षा का शपथ पत्र लेकर खड़ा है, तो इस अकेले प्रयास से शायद ही भूमिका बदलेगी। शिक्षा के अपने इन्स्थिहान उसी इमारत में असफल इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर और पदोन्नतियों में ही पूरा महकमा अतरंगी हो गया। व्यवस्था की नौटकी में शिक्षक समाज अपनी प्राथमिकताओं को ऐसे स्थानांतरण से मजबूत कर रहा है, जो एक तरह का राजनीतिक गठबंधन है। हर राजनीतिक पार्टी और नेताओं के समूह इस तलाश में रहते हैं कि उनके अपने और चहेते शिक्षक ही नजदीकी स्कूलों में शिरकत करें। सुक्ष्म सरकार ने भी ट्रांसफर के दायरे बढ़ाते हुए कुछ किलोमीटर मापे, लेकिन करवटे बताती हैं कि व्यवस्था के भीतर अध्यापक चंद किलोमीटर की परिधि में घमघम कर चहरे बदल रहे हैं।

